रक्षा कर्मियों को निजी कोठियों का आबंटन

808. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मेरठ छावनी में निजी कोठियों को रक्षा मंत्रालय के कर्मियों को आवंटित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि रक्षा कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बावजूद उन्होंने उक्त कोठियां उनके स्वामियों अथवा विभाग के सुपुर्द अभी तक नहीं की हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडिस): (क) और (ख) जी, हां। इस समय मेरठ छावनी में 12 पुराने बड़े बंगले हैं जो सेना के पास हैं। ये बंगले सेना कार्मिकों/रक्षा सिविल कर्मचारियों को आवास के रूप में आबंटित किए हुए हैं। इस समय इन बंगलों में सेना कार्मिक रह रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

असैनिक कार्यों के लिए रक्षा कार्मिकों की तैनाती

809. **श्री गोविन्दराम गिरी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कितने रक्षा कार्मिकों को असैनिक कार्यों में लगाया गया है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि असैनिक कार्यों के लिए रक्षा कार्मिकों का कम से कम उपयोग हो;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(घ) इस स्थिति के संबंध में समय-समय पर समीक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडिस): (क) सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए हमारे 2 लाख सेना कार्मिक प्रति विद्रोही कार्रवाइयों में लगे हुए हैं।

(ख) और (ग) ऐसे कार्यों पर रक्षा कार्मिकों की तैनाती काफी विचार-विमर्श के पश्चात् ही की जाती है इस संबंध में नीति संबंधी दिशा-निर्देश यह है कि सेना कार्मिकों को विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप तभी तैनात किया जाना चाहिए जब सिविल प्रशासन अपने संसाधनों से स्थिति से निपटने में सक्षम न हो।

(घ) ऐसे क्षेत्रों में स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा जब भी यह महसूस किया जाता है कि अब सेना की आवश्यकता नहीं है और अर्ध सेना बल तथा राज्य पुलिस स्थिति को संभाल सकते हैं तो सेना को हटा लिया जाता है।

Voluntary retirements in Navy

810. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned, "Voluntary retirement increasing in Navy Officers see green pastures outside" appearing in the Times of India dated January 12, 1999;

(b) if so, the details of officers who sought voluntary retirement during last three years, year-wise;

(c) whether it is a fact that the Directorate of Ex-Servicemen Association situated at South Block, is instrumental in arranging such green pastures, particularly for the naval officers; and

(d) whether Government would consider shifting the DESA from South Block, to curb such exodus?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (d) The news item captioned "Voluntary retirement increasing in Navy Officers see green pastures outside" appeared in the Times of India dated January 1999.

The details of Navy Officers who sought voluntary retirement during the last three years are as follows:—

1996 : 105
1997 : 134
1998 : 192

The requests for premature retirements submitted by Naval officers, duly recommended by the Chief of Naval Staff, are considered by the Government on the basis of the guidelines issued by the Government from time to time. Each case is decided by the Government on its merits. The Directorate of Ex-Servicemen Affairs, Naval Hqrs., has no role to play

in the premature release of Naval Officers.

The Directorate of Ex-Servicemen Affairs, Naval Hqs. is not located in South Block.

Use of Indian satellite by IAF

811. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:
SHRI RAGHAVJI:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether IAF is using Indian Satellites to keep a watch on all potentially hostile countries as reported in the Asian Age of 30th December, 1998; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) The Indian Space Programme is well developed. Its satellites photograph surface area. The data from these satellites are also being used for defence requirements. These satellites have cameras capable of panchromatic and multi-spectral photography. The resolution is 5.8M for panchromatic and 23.5M for multi-spectral camera. However, it would not be desirable to reveal specific details in the interest of security.

पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी

812. श्रीमती मालती शर्मा:
प्रो॰ रामबक्ष सिंह वर्मा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में अनेक बार गोलाबारी की गई;

(ख) यदि हां, तो इस गोलाबारी से जान-माल की कितनी हानि हुई; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडिस): (क) से (ग) जम्मू-कश्मीर में भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अकारण गोलीबारी की जाती रही है। वर्ष 1997 और 1998 के दौरान गोलीबारी की इन घटनाओं में सेना के 99 कार्मिक, सीमा सुरक्षा बल के 13 कार्मिक तथा 72 सिविलियन मारे गए और सेना के 408 कार्मिक, सीमा सुरक्षा बल के 59 कार्मिक तथा 204 सिविलियन जख्मी हुए।

हमारे सैनिकों द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों की अकारण गोलीबारी का समुचित जवाब दिया जाता है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि गोलीबारी की ये घटनाएं क्षेत्र विशेष तक सीमित रहें और इस जवाबी गोलीबारी में कोई सिविलियन हताहत न हो और हमारी ओर से की जाने वाली ये जवाबी कार्रवाईयां दण्डात्मक व प्रभावी साबित हों।

Modernisation of Police Forces of Insurgency affected States

813. SHRI KHAGEN DAS: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are providing any assistance to the insurgency affected States for modernising police forces; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) "Police" being a State subject as per the Constitution of India, it is primarily the responsibility of the State Governments to adequately equip their police forces. The Central Government however, supplements the efforts of the State Governments by providing them financial assistance under the Scheme for Modernisation of State Police Forces. The amount released to the insurgency affected States in the North-East during 1997-98 and 1998-99 was Rs. 9.85 crores & Rs. 7.37 crores respectively.

Besides the assistance under the Scheme for Modernisation of State Police Forces, North-Eastern States were